# ग्रामीण विकास की योजनाएं

## मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल.आवास योजना

निर्धन को आवास का सपना पूरा करने के लिए लागू की गई मुख्यमंत्राी ग्रामीण बी.पी.एल.आवास योजना के अंतर्गत जिले में अभी तक 7 हजार 425 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। योजना के अंतर्गत जिले को चालू वित्तीय वर्ष में 42 हजार 39 आवासों के निर्माण के लक्ष्य का आवंटन किया गया था जिसके विपरीत अभी तक 90 करोड़ रुपये की राशि से 36 हजार 905 आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा प्रथम किश्त की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तानान्तरित की जा चुकी हैं। शेष रहे लाभार्थियों के लिए जिले को हुडको से अक्टूबर माह के अंत में 8 करोड रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिनकी स्वीकृतियां जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्राी आवास योजना के तहत 29 हजार 601 शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई।

## इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के 705, अनुसूचित जनजाति के 3604, अल्पसंख्यक वर्ग के 918 तथा सामान्य वर्ग के 1502, कुल 6729 लाभार्थियों को आवास निर्माण का लाभ दिया गया, जिस पर 3243.08 राशि व्यय हुई।

## स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत तीन वर्षों में 1641 स्वयं सहायता समूहों के कुल 18594 सदस्यों को लाभान्वित किया गया तथा व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत 1052 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। योजना के तहत 5724.70 लाख ऋण/अनुदान दिये जाकर 1967 अनु. जाति, 11867 अनु. जनजाति, 6172 सामान्य वर्ग, 13432 महिलाऐं, 556 विकलांग एवं 1269 अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों को लाभान्वित किया गया।

# सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

## संसदीय क्षेत्र - उदयपुर

सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्रा उदयपुर में गत तीन वर्षों में कुल 485 कार्य 510.63 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई। 336 कार्य पूर्ण करा 322.57 लाख का व्यय किया गया ।

## संसदीय क्षेत्र - चित्तौड़गढ़

सांसद स्थानीय क्षेत्रा विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्रा चित्तौड़गढ़ में गत तीन वर्षों में कुल 92 कार्यों के लिये 153.98 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई। 30 कार्य पूर्ण करा 69.89 लाख का व्यय किया गया ।

# विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

विधायक क्षेत्राीय विकास योजनान्तर्गत तीन वर्षों में 1271 कार्यों पर 1196.29 लाख रू. व्यय किए जाकर 937 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं।

# स्व-विवेक जिला विकास योजना

स्व- विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में कुल 22 कार्य 60.24 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई। 15 कार्य पूर्ण करा 39.86 लाख व्यय किये गये।

# ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में कुल 7 कार्य 25.20 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई । 6.90 लाख का व्यय किया गया ।

# नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आंगनवाड़ी योजना

नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आगंनवाड़ी केन्द्र की गत तीन वर्षों में कुल 14 कार्य 42.28 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की गई।

माडा एवं बिखरी योजना

माडा एवं बिखरी योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत माडा में 217.872 लाख एवं बिखरी में 200.69 लाख का व्यय हुआ।

## जनजाति कल्याण निधि

तीन वर्षों में जनजाति कल्याण निधि (महाराष्ट्र पैटर्न) योजनान्तर्गत माडा में 198.94 लाख एवं बिखरी में 116.45 लाख का व्यय हुआ।

## पंचायतीराज योजनाएं

### पिछड़ा क्षेत्रा अनुदान कोष

पिछड़ा क्षेत्रा अनुदान कोष अन्तर्गत तीन वर्षों में जिले में 3484 कार्यो की स्वीकृतियां जारी की गई। इन कार्यों में से 2246 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों पर अब तक राशि रू. 6057.63 लाख रू. व्यय किए गए है।

### बारहवां वित्त आयोग

बारहवां वित्त आयोग अन्तर्गत तीन वर्षों में जिले में 3508 कार्यो की स्वीकृतियां जारी की गई। इन कार्यो में से 2793 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यो पर अब तक राशि रू. 2118.77 लाख रू. व्यय किए गए हैं।

### तेरहवां वित्त आयोग

तेरहवां वित्त आयोग अन्तर्गत तीन वर्षों में जिले में 2095 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई। इन कार्यो में से 1536 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्या पर अब तक राशि रू. 1562.64 लाख व्यय किए गए हैं।

### राज्य वित्त आयोग-तृतीय

राज्य वित्त आयोग तृतीय अन्तर्गत तीन वर्षों में जिले में 5292 कार्यो की स्वीकृतियां जारी की गई। इन कार्यों में से 4920 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों पर राशि रु. 1217.17 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान ;च्ल्ज्ञ।द्ध

पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान अन्तर्गत तीन वर्षों में जिले में 32 विद्यालयों में खेल मैदान निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। इन कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यो पर राशि रू. 20.40 लाख व्यय किए गए हैं।

### भूखण्ड आवंटन

पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157, 157(2) एवं 158 के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक कुल 10325 परिवारों को पट्टे जारी किए गए हैं।

### सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 1380.37 लाख रु. व्यय करते हुए 59,168 चयनित परिवारों के

घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाया गया। 170.20 लाख रु. खर्च करते हुए 851 विद्यालयों में शाला शौचालय का निर्माण कराया गया। 22.60 लाख रू. व्यय कर 435 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बेबी फ्रेण्डली शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा 12.00 लाख रु. व्यय करते हुए 12 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2011-12 में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत 37255 आवासों हेतु शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

## कथौड़ियों के लिए आवास

स्वच्छ परियोजना के अंतर्गत जिले के कथौड़ी समुदाय के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 100 नये आवास निर्माण स्वीकृत किए गए है जबकि इतने ही आवासों का निर्माण प्रगति पर चल रहा है। अब तक 67 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया हैं। आवास निर्माण कार्यों पर 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई जिसके विपरीत 94.05 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले में परियोजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह के अंत तक 18 हजार 536 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया जिसमें 9 हजार 89 शौचालय बीपीएल परिवारों के यहां बनवाए गए। साथ ही 94 विद्यालयों एवं 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालयों का निर्माण कराया गया। कार्यक्रम में अभी तक 13.53 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं तथा वर्तमान में संस्थाओं को 5.94 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से उपलब्ध कराए गए। परियोजना प्रारंभ होने से लेकर अब तक जिले में कुल 2.07 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया जिसमें से 1.20 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण बीपीएल परिवारों द्वारा कराया गया।

वर्ष 2010 के लिए पंचायत समिति गोगुन्दा के चोरबावडी ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में निर्मल ग्राम के पुरस्कार हेतु 11 पंचायतों ने प्रस्ताव भिजवाए हैं।

# जलग्रहण विकास कार्यक्रम

## मरु विकास कार्यक्रम (DDP)

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 44 जलग्रहण परियोजनाएं प्रगतिरत थी। 487.10 लाख रूपये व्यय किये जाकर 31 परियोजनाऍं पूर्ण कर ली गई है एवं 13 परियोजनाएं प्रगतिरत है। किये गये व्यय के विरुद्ध 6563 हैक्टर क्षेत्रा उपचारित किया गया है।

## सूखा सम्भाव्य क्षेत्रा विकास कार्यक्रम (DPAP)

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 49 जलग्रहण परियोजनाएं प्रगतिरत थी। 706.58 लाख रुपये व्यय किये जाकर 40 परियोजनाऍं पूर्ण कर ली गई है एवं 9 परियोजनाऍं प्रगतिरत हैं। किये गये व्यय के विरूद्ध 9884 हैक्टर क्षेत्रा उपचारित किया गया है।

## एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में एक जलग्रहण परियोजना प्रगतिरत थी। 58.76 लाख रुपये व्यय किये

जाकर परियोजना पूर्ण कर ली गई है। किये गये व्यय के विरुद्ध 977 हैक्टर क्षेत्रा उपचारित किया गया है।

## राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना (NWDPRA)

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 22 जलग्रहण परियोजनाएं प्रगतिरत है। जिन पर 313.37 लाख रु. व्यय किये जाकर 2105 हैक्टर क्षेत्रा उपचारित किया गया है।

## जनजाति विकास विभाग द्वारा स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाएँ (TAD)

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 11 जलग्रहण परियोजनाएं प्रगतिरत थी। 119.08 लाख रुपये व्यय किये जाकर 7 योजनाएँ पूर्ण कर ली गई है एवं 4 परियोजनाएँ प्रगतिरत है। किये गये व्यय के विरूद्ध 2179 हैक्टर क्षेत्रा उपचारित किया गया है।

## एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (IWMP)

## वर्ष 2009-10

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 3 योजनाएं प्रगतिरत हैं। 133.12 लाख रुपये व्यय किये जाकर प्रारम्भिक गतिविधियां पूर्ण कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करा अनुमोदित करा लिया गया है। तद्नुसार क्षेत्रा में कार्य प्रगतिरत है।

## एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (IWMP) वर्ष 2010-11

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 4 योजनाएं प्रगतिरत थी। 99.14 लाख रुपये व्यय किये जाकर प्रारम्भिक गतिविधियां यथा प्रशिक्षण, आस्था मूलक कार्य, अध्ययन भ्रमण सम्पादित कर लिये गये हैं।

## एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (IWMP)

## वर्ष 2011-12

वर्ष 2011-12 में 5 जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत हुई है जिनमें प्रारम्भिक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गई है।

# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

## रोजगार गारंटी योजना

महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 62 हजार 452 परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए। योजना में 8.54 लाख से अधिक श्रमिकों को 785.13 लाख मानव श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। इनमें से 4 लाख 50 हजार 277 श्रमिकों ने सौ दिवस रोजगार पूर्ण किया। योजना में कुल 1454 करोड़ 86 लाख 59 हजार रुपये व्यय किए गए जिसमें मजदूरी के रूप में 954 करोड़ 87 लाख 66 हजार रुपये का भुगतान किया गया तथा सामग्री मद पर 499

करोड़ 98 लाख 93 हजार रुपये व्यय किए गए। योजना में एक लाख 5 हजार 604 कार्य स्वीकृत किए गए जिसमें से 63 हजार 373 कार्य पूर्ण हुए।

## राजीव गांधी सेवा केन्द्र

महानरेगा योजना में 11 पंचायत समितियों एवं 467 ग्राम पंचायतों पर भारत निर्माण राजीवगांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण के तहत सभी पंचायत समितियों एवं 425 ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

## मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम

बच्चों को शिक्षा से जोड़ने व उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से चलाए जा रहे मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कक्षा 1 से 8 तक के 4 हजार 370 विद्यालयों में 3 लाख 84 हजार 965 नामांकित बालक-बालिकाओं को पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा हैं। विद्यालयों को भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के अंतर्गत प्रथम चरण में 150 से अधिक नामांकन वाले 204 विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। पंचायत समिति गिर्वा, झाड़ोल, मावली, खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में ऐसे 332 विद्यालय पाए गए थे, जहां 150 से अधिक बच्चों का नामांकन हुआ। शेष विद्यालयों को शीघ्र ही गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 1425 विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन देना प्रस्तावित है। जिले के 1545 विद्यालयों में किचन शेड बनाने का कार्य भी पूरा कर दिया गया हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत भुवाणा (उदयपुर), सलूम्बर एवं झाड़ोल में नान्दी फाउण्डेशन द्वारा 3 केन्द्रीयकृत किचन संचालित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से इन क्षेत्राों के 1458 विद्यालयों के औसतन 80 हजार बच्चों को प्रतिदिन पोषाहार तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के 2898 विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा एवं 14 विद्यालयों में 3 महिला अन्नपूर्णा सहकारी समितियों द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

## नवजीवन योजना

राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को इस व्यवसाय से बाहर निकालकर ऐसे परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरु की गई नवजीवन योजना में आबकारी विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में 6 हजार 435 व्यक्तियों को प्रशिक्षण, स्वरोजगार, शिक्षा आदि गतिविधियों से जोड़कर लाभान्वित किया गया। इस योजना के तहत 750.98 लाख रुपये व्यय किए गए। आबकारी विभाग द्वारा 77.72 करोड़ 64 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। आबकारी विभाग द्वारा राज्य में पिछले तीन वर्षों में आबकारी अधिनियम के तहत 26140 अभियोग दर्ज कर 20 हजार 629 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1078 वाहन जब्त किए गए। जब्त किए गए वाहनों की

नीलामी से 1634.27 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। आबकारी नीति के अनुसार अन्य राज्यों से तस्करी होकर आने वाली मदिरा की रोकथाम के लिए मुखबिर को मदिरा के मूल्य के अनुपात में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। डोडा पोस्त की खरीद की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर पहले 100 रुपये एवं अब 125 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है। खुदरा दुकानों का संचालन रात 8.00 बजे तक सुनिश्चित किया जा रहा है।

## श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर

जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में 48 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया एवं वर्तमान में 684 समितियां पंजीकृत हैं जिनमें 7513 सदस्यों को सदस्यता दी गई है। वर्तमान में इन समितियों से औसत 70 हजार लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जा रहा हैं। पशुपालकों को अनुदानित दर पर 175 लाख रुपये का पशु आहार उपलब्ध कराया गया। सरस सुरक्षा कवच (जनश्री बीमा) योजना के अंतर्गत 434 सदस्यों को 81.33 लाख रुपये की दावा राशि एवं 547 छात्रा-छात्राओं को 6.564 लाख रुपये की छात्रावृत्ति का भुगतान कर लाभान्वित किया गया। दुग्ध संघ कार्यक्षेत्रा में 24 बीएमसी स्थापित किए गए जिनसे करीब 13 हजार लीटर प्रतिदिन दूध समितियों से ठण्डा होकर संघ तक पहुंच रहा हैं। डेयरी के क्षेत्रा में नवाचार के साथ दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट व वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में विगत तीन वर्षों में ट्रोमा सेंटर में आर्थोपेडिक आउटडोर, इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर एवं एक्सरे सुविधा मुहैय्या कराई गई है। ट्रोमा सेंटर के लिए 9.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। चिकित्सालय में 1.31 करोड़ रुपये की लागत से रिमोट कन्ट्रोल ब्रेक्रीथेरेपी मशीन एवं रेडिएशन सेफ्टी उपकरण क्रय कर केंसर नियंत्राण केन्द्र शुरु किया गया तथा 27 लाख रुपये से साइकोसोशियल रिहेबिलेशन सेंटर भी प्रारंभ किया गया।

बाल चिकित्सालय में नर्सरी भवन का निर्माण शुरु किया गया। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत येग लेजर से 50 लाख रुपये के 4 उपकरण प्राप्त हुए। हिन्दुस्तान जिंक/वेदान्ता के सहयोग से 10 करोड़ रुपये राशि से कॉर्डियोलॉजी विभाग का आधुनिकीकरण किया गया।

## मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

मुख्यमंत्राी निःशुल्क दवा वितरण योजना की 2 अक्टूबर,2011 से शुरुआत की गई। जिले में राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए 188 दवा वितरण केन्द्र बनाए गए हैं। वर्तमान में 180

दवाइयां वितरित की जा रही हैं जिनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, केंसर नियंत्राण व थॉयरॉयड जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं।

योजना के पहले दिन ही जिले में 8 हजार मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इनमें से 6 हजार 555 मरीजों को आउटडोर में तथा शेष मरीजों को इनडोर में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इनमें से 7 हजार 500 अर्थात करीब 95 प्रतिशत मरीजों को उनकी जरुरत की 100 प्रतिशत दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सामान्य बीमारियों के करीब 90 प्रतिशत से अधिक दवाइयां निःशुल्क चिकित्सालयों से वितरित की जा रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि एक भी मरीज को चिकित्सालय के बाहर से दवा नहीं खरीदनी पड़े। जिले में नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक 3.43 लाख रोगियों को आउटडोर में तथा 30 हजार से अधिक रोगियों को इनडोर में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई।

## माँ-राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना

सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जच्चा एवं बच्चा की देखभाल की सुनिश्चितता तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 12 सितम्बर से लागू की गई ''मॉं-राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना'' के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं व 30 दिवस तक के बच्चों को जिले के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क दवा एवं जांच, निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा प्रसूताओं को निःशुल्क भोजन मुहैय्या कराया जा रहा है। योजना के तहत अब तक राजकीय चिकित्सालयों में पांच हजार 762 महिलाओं के प्रसव सुरक्षित रूप से कराये जा चुके हैं।

योजना के अंतर्गत निःशुल्क परिवहन सुविधा के लिए 43 लाख रुपये महिलाओं हेतु तथा 15.10 लाख रुपये 30 दिवस तक शिशु की देखभाल के लिए आवंटित किए गए हैं। अब तक जिले में एक हजार 759 गर्भवती महिलाओं व 178 बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई जिस पर 1.90 लाख रुपये खर्च किए गए।

निःशुल्क दवाइयों की सुविधा मुहैय्या कराने के अंतर्गत 8 हजार 693 गर्भवती महिलाओं व 2 हजार 230 बच्चों को लाभान्वित किया गया। निःशुल्क दवाओं के लिए जिले को अभी तक 65.54 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया। इसमें से 27.50 लाख रुपये मेडिकल कॉलेज को हस्तान्तरित की गई तथा 22.54 लाख रुपये की दवाइयां क्रय कर चिकित्सा संस्थाओं पर उपलब्ध कराई गई।

जननी व शिशु सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना में अभी तक 5 हजार 334 गर्भवती महिलाओं एवं 346 शिशुओं की निःशुल्क जांच की गई तथा 6 हजार 387 प्रसूताओं को निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध कराई गई।

# मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष

वर्ष 2009 से प्रारंभ मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4 लाख 58 हजार 559 बीपीएल मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर 7.21 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

मिशन के प्रारंभ होने से लेकर अब तक जिले में 2 लाख 34 हजार 291 प्रसूताओं को संस्थागत प्रसव व जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित कर 32.23 करोड़ रुपये व्यय किए गए। बीपीएल प्रसूताओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देशी घी उपलब्ध कराने की योजना से 7 हजार से अधिक प्रसूताओं को लाभान्वित किया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जन को पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 995 आशा सहयोगिनी सेवारत हैं तथा 2465 गांवों में ग्राम स्वास्थ्य समितियों का गठन किया गया है। जिले में 80 मॉडल उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर 76.23 लाख रुपये व्यय किए गए जिसमें से 60 भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया हैं। मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अक्टूबर माह के अंत तक 88.69 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

# खान विभाग का योगदान

रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइमस्टोन एवं लिग्नाइट आदि खनिज सम्पदा के दोहन एवं विपणन में कार्य करने वाला राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स देश का प्रमुख प्रतिष्ठान है। जिले के साथ-साथ राज्य के विकास में संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले तीन वर्षों में संस्थान ने 5921 करोड़ 19 लाख 63 हजार रुपये का सकल व्यवसाय कर राजकीय कोष में 1146 करोड़ 11 लाख 19 हजार रुपये का महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्थान की वर्तमान में अधिकृत पूंजी 80 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त अंशपूंजी 77.55 करोड़ 15 हजार रुपये है।

संस्थान द्वारा विगत तीन वर्षो में 32.53 लाख मेट्रिक टन रॉक फॉस्फेट, 94.06 लाख मेट्रिक टन जिप्सम, 85.65 लाख मेट्रिक टन लाइम स्टोन तथा 27.67 लाख मेट्रिक टन लिग्नाइट का उत्पादन किया गया। जनहित कार्यों में योगदान करते हुए संस्थान ने 9.90 करोड़ रुपये का योगदान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया। खदान के समीपवर्ती गांवों के 500 जनजाति बाहुल्य छात्रों के लिए संचालित विद्यालय पर प्रतिवर्ष 51.50 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षा, चिकित्सा केम्प, सड़क मरम्मत एवं ग्रामीण विकास कार्यो पर संस्थान द्वारा अब तक 5.50 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

मत्स्यपालन को बढ़ावा

मत्स्यपालन को रोजगार से जोड़कर बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन विभाग द्वारा 41 व्यक्तियों को मत्स्यपालन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विगत तीन वर्षों में मत्स्य पालन के लिए 4 नये पौण्ड बनाये गये तथा 10 पौण्ड आवंटित किए गए। बीमे का लाभ दिलाने के लिए 3200 मत्स्यपालकों का समूह बीमा कराया गया। मछुआरों के लिए 40 आवासों का निर्माण किया गया। स्वच्छ जलाशय विकास कार्यों पर 26.45 लाख रुपये व्यय किए गए।

विगत तीन वर्षों में 576.07 फाई लाख मत्स्य बीज एवं 2432.28 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। मत्स्य ठेके से 436.96 लाख एवं मत्स्य बीज विक्रय से 5016 लाख रुपये की आय हुई। चालू वित्तीय वर्ष में 100 मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण देने व 100 हैक्टेयर में मत्स्यपालन के लिए नये तालाब आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 10 हैक्टेयर में तालाबों का आवंटन किया जा चुका है।

## औद्योगिक विकास

नये उद्योगों की स्थापना कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिले में 131 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। जिनमें 567 करोड़ 61 लाख 15 हजार रुपये का पूंजी निवेश किया गया। लघु एवं मध्यम 2015 नई इकाइयों का पंजीयन किया गया जिनसे 13 हजार 247 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु 152 युवाओं को विभिन्न बैंकों से ऋण सहायता उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया गया। स्वरोजगार हेतु घरेलू उद्योग योजना में 493 महिलाओं को विभिन्न 18 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 223 व्यक्तियों को औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ करने की जानकारी दी गई।

जिले में दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए 1687 दस्तकारों को पहचान पत्रा दिलाये गये। साथ ही 752 दस्तकारों को आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विभिन्न बैंकों से वित्त सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा दस्तकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 122 मेला प्रदर्शनियों का आयोजन कर रियायती दर पर जगह उपलब्ध ा कराई गई।

## वाणिज्यिक कर वसूली

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के समय में अब तक 1354 करोड़ 84 लाख 76 हजार रुपये का वेट राजस्व अर्जित किया गया। वर्ष 2008-09 में 264 करोड़ 35 लाख 1 हजार रुपये, वर्ष 2009-10 में 405 करोड़ 52 लाख 51 हजार रुपये, वर्ष 2010-11 में 412 करोड़ 1 लाख 93 हजार रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 272 करोड़ 95 लाख 31 हजार रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

## स्वच्छ पेयजल सुविधा विकास

पेयजल सुविधा विकास के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिाकी विभाग द्वारा पेयजल की विभिन्न योजनाओं पर विगत तीन वर्षों में 157.21 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। उदयपुर शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए 55 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्गठित जल वितरण योजना पूरी कर जलापूर्ति शुरू की गई। पंचायत समिति सलुम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, मावली एवं भीण्डर में जल को फ्लोराईड से मुक्त करने के लिए 285 फ्लोराइड आधिक्य बस्तियों में हैण्डपंप पर डी-फ्लोराइडेशन प्लान्ट स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 184 हैण्डपंपों के लक्ष्य के विपरीत अब तक 55 हैण्डपंपों पर डी-फ्लोराइडेशन प्लान्ट लगाए जा चुके हैं। जयसमन्द झील से 13 गांवों को पेयजल पहुंचाने की योजना को पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है।

जनजाति मद में जनजाति क्षेत्रा की पंचायत समिति खेरवाड़ा में पलसिया महुदरा, घाटी, बाघपुर व सुलई,

खुणादरी, पंचायत समिति सराड़ा में श्यामपुरा, पंचायत समिति सलूम्बर में माकड़सीमा जल योजनाएं पूर्ण कर चालू कर दी गई हैं। इन योजनाओं पर 175 लाख रुपये व्यय किए गए।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में 2854.17 लाख रुपये व्यय कर 227 योजनाएं पूरी कर पेयजल उपलब्ध कराया गया। इन योजनाओं से अनुसूचित जाति की 47, अनुसूचित जनजाति की 562 बस्तियों, 31 स्कूलों एवं 276 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेयजल से लाभान्वित किया गया।

पेयजल समस्या के निराकरण के लिए जिले में नये 869 हैण्डपंप एवं 28 नलकूप स्थापित कर चालू किए गए। हैण्डपंप मरम्मत अभियान के तहत कुल 50 हजार 456 हैण्डपंपों की मरम्मत की गई तथा आवश्यकता वाले हैण्डपंपों में 74 हजार 209 मीटर जीआई पाइप बढ़ाए गए। पेयजल समस्या ग्रसित गांवों, ढाणियों, बस्तियों में परिवहन कर जल उपलब्ध कराया गया जिस पर 837.30 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

## देवास योजना पर 247 करोड़ व्यय

साबरमती बेसिन के अतिरिक्त जल को उदयपुर शहर के लिए पेयजल हेतु डायवर्ट करने के लिए क्रियान्वित की जा रही मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना(देवास द्वितीय परियोजना) के अंतर्गत अब तक 247 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। योजना की मुख्य टनल की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया गया है एवं वर्तमान में आकोदड़ा बांध, मादड़ी बांध, लिंक टनल की खुदाई तथा मुख्य टनल की लाईनिंग का कार्य प्रगति पर चल रहा है।

योजना के अंतर्गत आकोदड़ा एवं मादड़ी में 2 बांध बनवाये जा रहे हैं। आकोदड़ा बांध की भराव क्षमता 302 एमसीएफटी एवं मादड़ी बांध की भराव क्षमता 85.44 एमसीएफटी है। दोनो बांधों की कुल भराव क्षमता 387.44 एमसीएफटी होगी। परियोजना से उदयपुर शहर की पिछोला झील को ग्रेविटी द्वारा पानी पहुंचाने हेतु आकोदड़ा बांध स्थल से कोडियात गांव तक 11.05 किलोमीटर एवं मादड़ी बांध से मुख्य टनल तक 1.21 किलोमीटर लंबी टनल (सुरंग) का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से उदयपुर की झीलों के लिए 549.63 एमसीएफटी जल ग्रेविटी के माध्यम से पहुंचाना प्रस्तावित है।

## समाज कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों में 20.63 करोड़ 96 हजार रुपये व्यय किए गए। उत्तर मेट्रिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग (देवनारायण योजना) वर्ग के 4495 छात्रा-छात्राओं को 687.62 लाख रुपये की छात्रावृत्ति उपलब्ध कराई गई। पालनहार योजना में अनाथ बच्चों के लालन-पालन के लिए 7754 पालनहारों को 240.55 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। निःशक्त कल्याण के तहत 757 निःशक्त बालकों को 10.14 लाख रुपये की छात्रावृत्ति से लाभान्वित किया गया। सहयोग योजना में 327, गाडिया लोहारों को आवास योजना में 196, अन्तर्जातीय विवाह योजना में 14, विकलांग विवाह योजना में 63, विधवा पुत्री की विवाह योजना में 83, स्वरोजगार की विश्वास योजना में 31 को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार निवारण के तहत अत्याचार से पीड़ित 75 व्यक्तियों को 16.152 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई।

## सामाजिक सुरक्षा (पेंशन)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं का जिले में 71 हजार 385 व्यक्ति (महिला–पुरुष) लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 15 हजार पेंशनर्स के डाकघर में बचत खाते खुलवाए जाकर खातों के माध्यम से पेंशन भुगतान के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। शेष पेशनर्स के भी जिला परिषद के माध्यम से खाते खुलवाए जाने की कार्ययोजना बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं ।

जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से 41 हजार 500, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन से 5 हजार 150, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन से 140 को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य वृद्धावस्था पेंशन से 4 हजार 675, राज्य विधवा पेंशन से 13 हजार 475 तथा राज्य निःशक्त पेंशन से 6 हजार 445 को लाभान्वित किया जा रहा है।

## आदिवासी उत्थान

जनजाति व्यक्तियों(आदिवासियों) के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में 460.54 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वनाधिकार अधिनियम के तहत 30 हजार 883 वनाधिकार पट्टे जारी किए गए। उच्च शिक्षा (महाविद्यालय) हेतु 16 हजार 582 जनजाति छात्राओं को तथा कक्षा 11 व 12 की 8 हजार 635 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के तहत सहायता प्रदान की गई। प्रतिभावान 5934 विद्यार्थियों को छात्रावृत्ति से एवं महाविद्यालय में अध्यनरत 24 हजार 243 जनजाति छात्रों को छात्रागृह किराये का पुनर्भरण की आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया गया। हिस्सा राशि के आधार पर निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में 42 हजार 681 छात्राओं को तथा 416 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की गई। बालिका शिक्षा के लिए 65 बालिका छात्रावास भवन तथा 8 आवासीय विद्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर चल रहा है।

कृषि के क्षेत्रा में 7 लाख 61 हजार 500 जनजाति कृषकों को निःशुल्क खाद एवं 3401 को निःशुल्क कृषि उपकरण वितरित कर लाभान्वित किया गया। उद्यानिकी विकास योजनाओं से 14 हजार 524 परिवारों को तथा उन्नत सब्जी विकास कार्यक्रम से 4055 काश्तकारों को तथा रेशम कीटपालन एवं मशरुम उत्पादन कार्यक्रमों से 800 परिवारों को लाभान्वित किया गया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4794 कुओं का विद्युतीकरण किया गया तथा पशुपालन क्षेत्रा में 119 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

जनजाति काश्तकारों को सिंचाई सुविधा मुहैय्या कराने के लिए जनजाति कृषकों के 2684 कुओं को ब्लास्टिंग से गहरा कराया गया, 2049 को डीजल पम्पसेट वितरित किए गए, 317 एनीकट बनाए गए तथा 42 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं निर्मित की गई।

आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 132 बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया, 533 हैण्डपंप लगाए गए, 299 सड़कें तथा 141 सामुदायिक भवन बनाए गए। स्वरोजगार हेतु 5104 को आर्थिक सहायता, 1176 महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता, 1384 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा 690 युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया।

## कृषि विकास

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विगत तीन वर्षों में प्रोजेक्ट गोल्डन रेज राजस्थान-2010 तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 4.33 लाख कृषकों को मक्का की संकर किस्मों के 21656.4 क्विन्टल प्रमाणित बीज वितरण कर लाभान्वित किया गया। विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बीपीएल जनजाति के 3.36 लाख से अधिक कृषकों को निःशुल्क उर्वरक उपलब्ध कराया गया। जिले में कुल उन्नत किस्म के बीजों के 84 हजार 960 मिनिकिट् वितरित किए गए। सिंचाई जल के कुशल प्रबंधन के तहत पाइपलाइन योजना में 574 किलोमीटर पाइपलाइन पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 11 हजार 302 उन्नत कृषि यंत्रा वितरित किए गए। वर्षा आधारित क्षेत्रा विकास कार्यक्रम में खरीफ-2011 में 10 हजार हैक्टेयर से अधिक मक्का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम में 3 हजार हैक्टेयर में 6 हजार ज्वार प्रदर्शन आयोजित कर 6 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया। फार्म पौण्ड निर्माण योजना में 6 काश्तकारों को 50 हजार रुपये प्रति काश्तकार अनुदान उपलब्ध कराया गया।

कृषकों को खरीफ एवं रबी में समय पूर्व कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए जिले की समस्त 467 पंचायतों पर कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में विगत तीन वर्षों में 80 हजार 270 बीज मिनिकिट्, 2936 मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 1046.27 क्विन्टल बीज, 4594 किसान क्रेडिट कार्ड एवं 1414 को जिप्सम का वितरण किया गया। पाइप लाइन के लिए 1394, उन्नत कृषि यंत्रों के लिए 8020, पौध सरंक्षण उपकरण के लिए 2872, फसल प्रदर्शन के लिए 4398 आवेदन पत्रा तैयार कराए गए। कृषकों को खेती संबंधी तकनिकी एवं उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए शिविरों में 30.25 लाख से अधिक प्रचार साहित्य का वितरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 2.18 लाख से अधिक पशुओं को कृमिनाशक औषधि तथा 29 हजार से अधिक मिनरल मिक्सर के पैकेट वितरित किए गए एवं 1.61 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।

## ग्वारपाठा लाया खुशहाली

ग्वारपाठा (एलोविरा) की खेती अब मुनाफे का व्यवसाय बनने लगी है। उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाड़ोल के छोटे से गांव नकोडिया के आदिवासी किसानों की तकदीर बदलने का सबब बन रही हैं ग्वारपाठे की खेती।

जब यहां के किसानों को ग्वारपाठे की उपयोगिता का पता चला तो किसान इसके लिए पहल कर आगे आए और गांव में 12 लाख ग्वारपाठे लगाए गए। राजस्थान कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आगे आकर 3 स्वयं सहायता समूहों को ग्वारपाठे का ज्यूस निकालने का विधिवत प्रशिक्षण दिया।

समीप के ओगणा गांव में ग्वारपाठा ज्यूस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई। इस केन्द्र में तैयार किया जाने वाला ग्वारपाठा ज्यूस अन्तर्राष्ट्रीय मानक को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा हैं। इस ज्यूस के औषधीय गुणों से देश-विदेश में इसकी काफी मांग भी है।

ओगणा में ग्वारपाठा ज्यूस से आदिवासी कृषकों को वर्ष 2009-10 में जहां 2 लाख 48 हजार रुपये की आय हुई थी वह वर्ष 2010-11 में बढ़कर 5 लाख 72 हजार रुपये हो गई। इस वर्ष 4 हजार 400 लीटर ग्वारपाठे का ज्यूस निकाला गया। मशीनी उपयोग से ज्यूस निकालने की क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है और

वर्ष 2011-12 में अब तक 1950 लीटर ज्यूस से 2 लाख 50 हजार रुपये की आय हो चुकी हैं।

यही नही मशीनीकरण के युग में जहां इन आदिवासी कृषकों के घरों में ग्वारपाठा के ज्यूस से समृद्धि आई है वहीं गुजरात से अगरबत्ती स्टिक बनाने की मशीन लगने से भी इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने में सहायता मिली है। पहले जहां आदिवासी कथौड़ी परिवार पूरे दिन की मेहनत कर हाथ से 50 से 100 रुपये की आमदनी करते थे, अब वे मशीन आने पर प्रतिदिन 400 रुपये तक की कमाई करने लगे हैं। वन विभाग द्वारा कथौड़ी परिवारों एवं वन सुरक्षा समितियों को यह मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। हाल ही में इनके द्वारा तैयार की गई 9 टन अगरबत्ती स्टिक के 2 ट्रक अहमदाबाद भेजे गए हैं। आज यहां के आदिवासी निश्चित ही ग्वारपाठा की खेती और अन्य साधनों से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुए हैं।

## सहकारिता

काश्तकारों को कृषि कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के तहत सहकारिता विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कुल 272 करोड़ 48 लाख 46 हजार रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए। इनमें से 248 करोड़ 46 लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण, 15.43 लाख के मध्यकालीन ऋण तथा 8.59 लाख के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए गए। जिले में 165 नई सहकारी समितियों तथा 859 सहकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन किया गया। सहकारी विभाग द्वारा 150 करोड़ 97 लाख 48 हजार रुपये का उपभोक्ता व्यवसाय विगत तीन वर्षों में किया गया। साथ ही 34.63 करोड़ रुपये का कृषि आदान व्यवसाय एवं 481.89 लाख रुपये का कृषि उपज व्यवसाय किया गया।

जिले में एनसीडीसी के माध्यम से 5 वर्षीय समग्र सहकारी विकास परियोजना स्वीकृत की गई जिसके अंतर्गत सितम्बर,2011 में 26.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई हैं। परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा हैं। वर्ष 2010-11 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 25 लेम्पस का गठन किया गया।

## पशुधन विकास

पशुधन विकास एवं पशुपालकों को नवीनतम तकनिकी पशुपालन की जानकारी देने के लिए जिले में पिछले तीन वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लिए 6226 पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर 1 लाख 47 हजार 909 पशुओं का उपचार किया गया। चिकित्सा संस्थाओं को शामिल कर जिले में कुल 6.48 से अधिक पशुओं का उपचार किया गया तथा 1 लाख 12 हजार 378 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। विभाग द्वारा 1381 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान एवं 4159 पशुओं का बांझपन निवारण किया गया। जिले में 1.60 हजार से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया। पशुपालकों के लिए 6223 गोष्ठियों का आयोजन किया गया। पशुपालकों को बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए 1159 भेड़ एवं गायों का बीमा कराया गया।

विगत तीन वर्षों में प्रथम श्रेणी के 4 पशु चिकित्सालयों, 5 पशु चिकित्सालयों, 8 पशु औषधालयों को क्रमोन्नत किया गया। जिले में 5 नये उप केन्द्र, 3 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 1 पशु चिकित्सालय स्वीकृत किए गए।

# विद्युत विस्तार

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा केन्द्र सरकार की आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अंतर्गत शहरी विद्युत तंत्रा को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के लिए 47.43 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। योजना के तहत नये 33 के.वी.सबस्टेशन, 33 के.वी.फीडर तथा 11 के.वी.के फीडर मय वितरण ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य शामिल किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत 11 के.वी.कार्यो पर करीब 19.93 करोड़ रुपये, 11 के.वी.कार्यों पर 13.64 करोड़ रुपये तथा अन्य कार्यों पर 13.86 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। नये 33 के.वी. सबस्टेशन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना प्रक्रियाधीन हैं। योजना के शेष कार्यों को मार्च,2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

# 219 फीडर नवीनीकरण कार्य पूर्ण

फीडर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर माह के अंत तक 219 फीडर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना में 223 फीड़र सुधार का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था। शेष 4 फीडर सुधार का कार्य इसी माह के अंत तक पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

# घरेलू एवं कृषि कनेक्शन

चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह के अंत तक 6 हजार 489 घरेलू कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं तथा 1262 आवेदकों को शीघ्र कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। कृषि कनेक्शन नीति के तहत चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य श्रेणी के दिसम्बर,2008 तक के लंबित आवेदकों के प्रथम चरण में 1443 एवं द्वितीय चरण में 303 कुल 1746 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1533 को मांग पत्रा जारी कर दिए गए हैं। जिसमें से 1012 आवेदकों ने मांग पत्रा की राशि जमा करा दी है। विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता शाखा द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक विद्युत चोरी के 5 हजार 853 प्रकरणों की जांच कर 115.60 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण कर 64.08 लाख रुपये की वसूली की गई।

उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए उपखण्ड स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को विद्युत चौपाल का आयोजन किया जा रहा हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 171 विद्युत चौपाल आयोजित कर 1161 विद्युत संबंधी शिकायतों का निराकरण किया गया।

# राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिले के शेष रहे विद्युत रहित ढाणियों को विद्युतीकृत करने एवं बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 89.13 करोड़ रुपये की एक पूरक योजना तैयार की गई हैं। इस योजना में 1503 ढाणियों एवं 33 हजार 887 बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उदयपुर जिले में अब तक 235 अविद्युतीकृत गांवों एवं 677 ढाणियों का विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले 78 हजार 434 परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत जिले को अप्रेल,2008 में 90.57 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए थे।

## ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना

जिले में ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अंतर्गत 33/11 के.वी.के 76 सब स्टेशनों की स्वीकृति वर्तमान सरकार के समय में अक्टूबर माह के अंत तक प्राप्त हुई। इसके तहत पंचायत समिति कोटड़ा में 4, गोगुन्दा में 7, मावली में 8, बड़गांव में 2, झाड़ोल में 6, सलुम्बर में 10, खेरवाड़ा में 11, गिर्वा में 6, भीण्ड़र में 10, लसाड़िया में 3 एवं सराड़ा में 9 सब स्टेशन स्वीकृत किए गए। इनमें से अक्टूबर,2011 तक 37 सब स्टेशनों का कार्य पूरा कर लिया गया हैं। कुल स्वीकृत 76 में से 59 सब स्टेशन जनजाति क्षेत्रा में स्वीकृत हुए जिनमें से 19 का कार्य पूरा हो गया हैं।

## राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधि ानियम-2011

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत जिले में अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सप्ताह में 2 हजार 23 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। योजना में कुल 3 हजार 120 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें पूर्व में विचाराधीन 1561 प्रकरणों को दर्ज कर शामिल किया गया एवं 1559 नये प्रकरण दर्ज हुए। शेष रहे 1097 प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा 260 को लेण्ड रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध कराई गई, 6 का कृषि भूमि नामान्तरण एवं 84 को कन्वर्जन सेवाएं प्रदान की गई। जलदाय विभाग द्वारा 19 हैण्डपम्प ठीक कराये गये, 66 नये जल कनेक्शन जारी किये गये, एक प्रकरण में जलापूर्ति खराबी को ठीक किया गया, 5 पानी के बिल ठीक किये गये, दो मीटर बदले गये तथा दो मामलों में धरोहर राशि लौटाई गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 165 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 44 को विधवा पेंशन तथा 13 को राज्य विधवा पेंशन स्वीकृत की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा 12 मीटर बदले गये। गृह(पुलिस) विभाग द्वारा 23 का सर्विस सत्यापन, 258 को पासपोर्ट के लिए सत्यापन, 340 का आर्म्स लाइसेंस नवीनीकरण के लिए सत्यापन किया गया। यातायात विभाग द्वारा 290 लर्निंग लाइसेंस, 208 स्थाई लाइसेंस, 9 डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किये गये एवं 239 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 2 को विकलांगता प्रमाण पत्रा एवं 13 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई। स्वायत्तशासन विभाग द्वारा 4 अनुज्ञापत्राों का नवीनीकरण, 5 भवनों के नक्शों की स्वीकृति, 10 जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रा, 2 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्रा जारी किये गये।

## सड़क विकास

सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण, डामरीकरण के अंतर्गत जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में 12.806 करोड़ रुपये से 845.74 किलोमीटर सड़कों के 298 कार्य स्वीकृत किए गए। इस अवधि में 59.74 करोड़ 95 लाख रुपये व्यय कर 397.27 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण

के कार्य पूर्ण कराए गए तथा शेष कार्य प्रगति पर एवं प्रक्रियाधीन है।

जिले में नये दस गांव तोरणा तालाब, जसपुरा, तिनसरा, सारी, चणा की उमर, भूतवड़, शिवड़ियों का चौराहा, उमरा, एकलिंगपुरा एवं तोरणा को डामर की सड़क से जोड़ा गया।

प्रधानमंत्राी ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 एवं इससे अधिक आबादी की बसावट वाले गांवों को डामर की सड़क से जोड़ने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 153.31 करोड़ 88 लाख रुपये के 441.35 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाने के लिए 134 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों की निविदा प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है। जिले में प्रधानमंत्राी सड़क योजना में योजना के प्रारंभ से अब तक 465 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय कर 857 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

## महिला एवं बाल कल्याण

महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्रा में जिले में महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में ऋषभदेव एवं झल्लारा में दो नई बाल विकास परियोजनाएं, 470 नये आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 153 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए। सेवाओं को त्वरित एवं प्रभावी बनाने के लिए 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 23 महिला पर्यवेक्षक, 470 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 153 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 470 आंगनवाड़ी सहायिका एवं इतने ही आशा सहयोगिनी के नये पद स्वीकृत किए गए।

जिले में कुल 14 बालविकास परियोजनाओं के 3140 आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा 2 लाख 59 हजार 221 बच्चों को पूरक पोषाहार से तथा 3 से 6 वर्ष आयु के 81 हजार 565 बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा से लाभान्वित किया जा रहा है। वेदान्ता फाउण्डेशन के माध्यम से गिर्वा, मावली, सराड़ा, भीण्डर, कोटड़ा एवं झाड़ोल की 6 परियोजनाओं में 600 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन हिन्दुस्तान जिंक के सहयोग से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने के लिए अभी तक 296 आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जा चुका है।

विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए जिले में 26 जनवरी,2011 से ''राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना '' संबला का शुभारंभ किया गया। इसके तहत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 11 से 15 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं के साथ-साथ 15 से 18 वर्ष की ऐसी बालिकाएं जो मध्याह्न पोषाहार से लाभान्वित नहीं है को 2 प्रीमिक्स हलवा एवं 2 उपमा (नमकीन) के पाउच घर ले जाकर उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर माह में एक दिन स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कर टीकाकरण एवं गर्भवती महिला की जांच तथा पोषण सलाह प्रदान करने का कार्य नियमित किया जा रहा है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

## शिक्षक अतिथि गृह-अभिनव योजना

जिले के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रा की झाड़ोल, खेरवाड़ा, कोटड़ा, लसाड़िया, सलुम्बर एवं सराड़ा पंचायत समितियों में शिक्षा का विकास करने और सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर ने पहल कर '' शिक्षक अतिथि गृह '' की एक अभिनव योजना तैयार की है, जिसे राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र द्वारा मंजूर कर लिया गया है।

इस अनूठी योजना में शिक्षकों को आवासीय सुविधा निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा प्रति माह योजना संचालन के लिए 6.64 लाख रुपये व्यय होंगे। विद्यार्थी छात्राावासों की तर्ज पर बनाई गई योजना में शिक्षकों को निःशुल्क आवास, भोजन एवं विद्यालय तक आने-जाने के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। योजना के प्रथम चरण में 160 शिक्षकों के लिए व्यवस्था की जाएगी।

## सर्वशिक्षा अभियान

शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण, अध्यापकों को प्रशिक्षण, विद्यालयों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने, वैकल्पिक शिक्षा, बालिका शिक्षा उन्नयन आदि प्रवृत्तियों पर पिछले तीन वर्षों में सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से 332 करोड़ 52 लाख 91 हजार रुपये व्यय किए गए।

अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत 63 हजार 779 विद्यालयों में विविध गतिविधियों पर 18.80 करोड़ 26 हजार रुपये व्यय किए गए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 22 हजार 823 शिक्षकों के प्रशिक्षण पर 157.72 लाख रुपये व्यय किए गए। वैकल्पिक शिक्षा के तहत शिक्षा से वंचित अनामांकित एवं ड्रॉपआउट 4650 बालक-बालिकाओं को आवासीय एवं गैर आवासीय शिविरों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले 120 बालकों को स्कूल रेडिनेशन शिविरों से जोड़ा गया तथा आवश्यकतानुसार 221 बालकों के लिए कृत्रिम उपकरण की व्यवस्था की गई। एस्कोर्ट भत्ता एवं परिवहन भत्ता से 217 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

नवाचारी गतिविधियों के तहत सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से अनुसुचित जाति एवं जनजाति की कक्षा 6 की 49 हजार बालिकाओं को कॉपियों का वितरण कराया गया। कम्प्यूटर शिक्षा 191 विद्यालयों में उपलब्ध ा कराई तथा 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खेल उपकरण लगाए गए। प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के उन्नयन के लिए 322 मॉडल क्लस्टर विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा में समुदाय की भागीदारी जोड़ने के उद्देश्य से 3861 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है।

ड्रॉप आउट, अनामांकित व दूरस्थ विद्यालयविहीन क्षेत्रा की बालिकाओं की शिक्षा हेतु जिले में 9 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा हैं जिनमें 800 बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय एवं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन विद्यालयों के संचालन पर 362.56 लाख रुपये व्यय किए गए।

विद्यालय भवनों के रख-रखाव के लिए 312 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 47 हजार 655 मीटर चारदीवारी, 75 विद्युतीकरण कार्य, 99 रेम्प मय रेलिंग, 115 रेम्प मरम्मत की स्वीकृतियां चालू वित्तीय वर्ष में जारी की गई। समस्त विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी स्वीकृतियां जारी की गई। विगत तीन वर्षो में विद्यालय भवनों के रख-रखाव विविध 10 हजार 462 कार्यो पर 46.97 करोड़ 77 हजार रुपये की राशि व्यय की गई।

# साक्षरता भारत मिशन–2012

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा (साक्षर भारत मिशन) के अंतर्गत 449 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में एक लोक शिक्षा केन्द्र प्रारंभ कर केन्द्र पर पर 2 प्रेरक नियुक्त किए गए हैं। केन्द्रों पर 40 हजार 510 असाक्षरों को पठन–पाठन का कार्य कराया जा रहा है। कार्यक्रम में 549 संदर्भ व्यक्तियों तथा 3945 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। असाक्षरों के लिए शिक्षण सामग्री क्रय करने पर 10.27 लाख रुपये व्यय किए गए। चालू वित्तीय वर्ष में लोक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए 89.80 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। कार्यक्रम पर प्रभावी निगरानी के लिए जिला, ब्लॉक स्तर की समितियों का गठन किया गया है।

# देवस्थान

देवस्थान विभाग द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के रख–रखाव एवं विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में 16.56 करोड़ 19 लाख रुपये के 211 कार्य स्वीकृत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष में 57 मंदिरों के लिए 9.37 करोड़ रुपये के 57 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में 64.45 करोड़ तथा चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी मंदिर में 42.53 करोड़ रुपये के कार्य विगत तीन वर्षों में कराए गए। विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में 19.09 करोड़ 38 लाख रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया।

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मंदिरों की भोग की राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। धार्मिक स्थलों के लिए मेला प्राधिकरण का गठन किया गया। अमरनाथ यात्राा पर राज्य से जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना के तहत विभाग को 4.00 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया।

# अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी

सरकार की महत्वपूर्ण योजना अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास द्वारा 500 आवास गृह निर्माण की योजना बनाई गई है। इस योजना में 11.46 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं।

प्रन्यास द्वारा दक्षिणी विस्तार योजना के प्रथम चरण में ई.डब्ल्यू.एस. के 200 तथा द्वितीय चरण में ई. डब्ल्यू.एस. के 196 व एल.आई.जी.के 194 आवास गृहों के निर्माण पर 8.50 करोड़ रुपये व्यय किए गए। लॉटरी निकाल कर इन आवासों का आवंटन किया जा चुका है। इसी योजना में लॉटरी पद्धति से आरक्षित दरों पर 800 भूखण्डों का आवंटन भी किया गया।

नगर विकास प्रन्यास द्वारा शहर के सौन्दर्यीकरण, सुविधा विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास आदि कार्यों पर पिछले तीन वर्षों में 114 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्तमान में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रन्यास द्वारा पिछोला झील एवं फतहसागर झील संरक्षण के कार्य कराये जा रहे हैं। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 84.75 करोड़ एवं

41.86 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दोनों योजनाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा हैं। पिछोला झील संरक्षण कार्यों पर 7.16 करोड़ तथा फतहसागर झील संरक्षण कार्यों पर 15.70 करोड़ रुपये अब तक व्यय किए जा चुके हैं।

फतहसागर झील की मुख्य पाल के पास बहुद्देश्यीय विभूति पार्क का निर्माण कराया जा रहा है जिस पर अभी तक 4.70 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

उदयपुर शहर के सीवरेज की समस्या के निस्तारण के लिए 65 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई हैं। योजना में सीवरेज को इकट्ठा कर मनवाखेड़ा गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट(एसटीपी) बनाया जाना प्रस्तावित हैं। योजना के लिए डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

आयड़ नदी पर बेदला पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिस पर 2.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। शहर के प्रमुख मार्गों के सौन्दर्यीकरण एवं विद्युत लाईनों को हटाकर भूमिगत केबल्स डालने के कार्य पर 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाकर 28 किलोमीटर केबल लाइनें डाली गई है।

पिछोला झील को भरने वाली सीसारमा नदी पर 4.81 करोड रुपये से एक नई पुलिया का निर्माण किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के समान महाराणा प्रताप खेल गांव का निर्माण प्रन्यास द्वारा कराया जा रहा है, जिस पर अभी तक 9 करोड़ 65 लाख 23 हजार रुपये व्यय किए जा चुके हैं। अभी तक खेल गांव में मुख्य स्टेडियम का निर्माण कर हैण्डबॉल, खो-खो, रायफल शूटिंग, टेनिस, वालीबॉल, कबड्डी, जूडो-कराटे, बॉक्सिंग, तैराकी, बॉस्केटबॉल, तीरन्दाजी एवं स्क्वेश कोर्ट के कार्य कराये जा चुके हैं।

विविध विकास कार्यों के तहत 2 पुलों के निर्माण 6.26 करोड़ रुपये, 15.50 किलोमीटर विद्युत कार्यों पर 3.77 करोड़ रुपये, रोड़ लाइट कार्यों पर 5.35 करोड़ रुपये, सीवरेज कार्यों पर 25 लाख रुपये, पेयजल कार्यों पर 1.80 करोड़ रुपये, 134.50 किलोमीटर सड़क निर्माण, नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्यों पर 45.07 करोड़ रुपये, 352 आवास निर्माण कार्य पर 6.18 करोड़ रुपये एवं उद्यान विकास के 18 कार्यों पर 6.28 करोड़ रुपये व्यय किए गए। प्रन्यास द्वारा 2 श्मशान घाटों एवं 6 विद्यालयों में विकास कार्य भी कराए गए। अन्य विविध कार्यों पर 22.43 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

## गतिमान प्रशासन-अनूठी पहल

सरकार की मंशा के अनुरूप कोटड़ा के इस आदिवासी दूरस्थ अंचल में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए उदयपुर के जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा ने अभिनव पहल कर ''गतिमान प्रशासन'' योजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य भाग बस के अंदर चलने वाला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित मोबाइल ऑफिस तैयार हो चुका है। इसके निर्माण पर करीब 47 लाख रुपये व्यय किए गए है।

मोबाइल ऑफिस बस में आठ खण्ड एवं एक विशेष पंजीयन काउण्टर बनाया गया हैं। काउण्टर पर समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्रा का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन होने पर प्रार्थना पत्रा बस में संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा और वे यथासंभव मौके पर ही समस्या का समाधान करेंगे। बस में राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, महिला एवं बाल विकास, जलदाय, विद्युत, कृषि, पशुपालन, रसद आदि विभागों के अधिकारी अपने-अपने काउण्टर

पर कार्य करेंगे। बस में उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार के लिए एक अलग से काउण्टर भी बनाया गया हैं। मोबाइल ऑफिस में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, जनरेटर एवं सीवीटी, माइक, एलसीडी आदि की सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ ही काउण्टर पर आने वाले प्रार्थियों की सुविधा के लिए पंजीयन एवं काउण्टर सेवाओं का लाभ लेते समय छाया की विशेष व्यवस्था बस के साथ की गई है।

मोबाइल ऑफिस में दस्तावेजों में फोटो लगाने के लिए फोटोग्राफी काउण्टर भी बनाया गया है हाल ही लागू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के लिए भी एक काउण्टर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल ऑफिस जिले के भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर डिजाइन किया गया है।

इस योजना में विशेष प्रकार की एक बस से विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सप्ताह के प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर शिविर लगायेंगे। बुधवार के शिविर से पूर्व सोमवार एवं मंगलवार को तथा शुक्रवार के शिविर के लिए बुधवार व गुरुवार को संबंधित पंचायत के तथा आस-पास क्षेत्रा के पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, ए.एन.एम. जहां पर पद भरे हुए हैं वे उपस्थित रह कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी करेंगे और उनके आवेदन पूर्ण रुप से तैयार करवायेंगे। जिससे बुधवार व शुक्रवार को ग्रामीणों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का मौके पर ही निराकरण हो सके। मोबाइल ऑफिस शिविर में कोटड़ा क्षेत्रा के उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार आवश्यक स्टॉफ सहित आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का शिविर में ही तत्काल समाधान हो सके।

## राहत का जरिया बना संजीवनी प्रकोष्ठ

जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए सरकार की मंशानुरूप उदयपुर का '' संजीवनी प्रकोष्ठ '' व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं जन हित की समस्याओं के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा द्वारा एक वर्ष पूर्व जन समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए नवाचार के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय में गठित संजीवनी प्रकोष्ठ से अब तक एक हजार 441 प्रकरणों में कार्यवाही कर शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाई जा चुकी है।

विधवा मीरांबाई एवं चुन्नीबाई आज खुश है कि उन्हें गुजर-बसर के लिए पेंशन का आसरा मिला है। इन्होंने जब विधवा पेंशन के लिए अपने परिवार के भरण-पोषण करने की समस्या बताई तो यह प्रकरण संजीवनी प्रकोष्ठ में दर्ज किया गया। प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली का ही परिणाम रहा कि विकास अधिकारी मावली द्वारा दोनों विधवा महिलाओं को पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किए गए और कोषाधिकारी द्वारा पेंशन अदायगी आदेश जारी कर दोनों को पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रकोष्ठ में प्रकरण दर्ज होने पर गांव उंखलियात तहसील कोटड़ा के कई श्रमिकों को भी उनकी मजदूरी का भुगतान होने से सन्तुष्टि मिली है। माणकावास गांव के श्यामलाल भी अपने कुए पर बिजली कनेक्शन मिलने से सकून महसूस कर रहे हैं। तहसील गिर्वा के ग्राम कानपुर निवासी एल.आर.चन्देल के दर्ज प्रकरण में हुई कार्यवाही से जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ। सलूम्बर के ग्राम कराकलां के कई लोगों की बीपीएल सूची में नाम जुड़ने से रह जाने की दर्ज शिकायत पर कार्यवाही की जाकर सलूम्बर के उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा सभी प्रार्थियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़ कर राहत दी गई। ऐसे अनेक लोगों

को प्रकोष्ठ से राहत मिली है।

प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक सुनिश्चित कार्य प्रणाली अपनाई जाती है। प्रकरण दर्ज होने पर संबंधित विभाग से निश्चित समय अवधि में प्रकरण का निस्तारण कर जवाब मांगा जाता है। प्राप्त जवाब के आधार पर कार्य पूरा होने वाले प्रकरणों का निपटारा कर दिया जाता है तथा जिन प्रकरणों के संबंध ा में कार्यवाही की जा रही होती हैं उन्हें अंतरिम जवाब मानते हुए लंबित रखा जाता है। निस्तारित किए गए प्रकरणों के संबंध में प्रार्थी को पोस्टकार्ड से सूचित किया जाता है।

पेयजल, विद्युत, अतिक्रमण, सफाई, कचरा निस्तारण, अवैध पार्किंग, चिकित्सा, प्रदूषण से संबंधित प्रकोष्ठ में दर्ज समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर जिला कलक्टर द्वारा बैठकें आयोजित कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्यवाही भी की जाती है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए की गई इस अनूठी पहल एवं अपनाई गई सुनिश्चित कार्य प्रणाली का ही परिणाम है कि नागरिकों में समस्याओं के प्रति प्रशासन के संवेदनशील होने का अच्छा संदेश पहुंचा हैं, जो सरकार मंशा भी है।

## नई सिंचाई परियोजनाएं

आजादी के 63 साल गुजरने पर भी उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्रा के 15 गांवों के आदिवासियों की आंखों में एक सपना तैरता है कि कब उन्हें पेयजल की अच्छी सुविधा मिलेगी और उनके खेतों को सिंचाई का पानी मुहैया होगा। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में साबरमती सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी जिससे इन आदिवासियों में आशा की एक किरण जागी है। इस योजना से कोटड़ा क्षेत्रा के क्यारा, बिकरनी, डेप, धध ामता, सांडमारिया, कोलिया, छापरिया, नयावास, कागवास एवं खजूरिया आदि पन्द्रह गांवों को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा मुहैय्या होगी।

29.50 करोड़ रुपये की इस परियोजना के निर्माण से अनुमान लगाया गया है कि 655 मिलियन घन फुट पानी पेयजल के लिए उपलब्ध होगा जिससे यहां की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। साथ ही इन गांवों में करीब 956 .85 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

इसी प्रकार कोटड़ा क्षेत्रा में ही रोहिणी गांव के पास 952.64 लाख रुपये से रोहिणी सिंचाई परियोजना भी स्वीकृत की गई हैं। इस परियोजना से अनुमान लगाया गया है कि 68 मिलियन घन फुट पानी कोटड़ा क्षेत्रा के मांडवा, कोदरमाल, बारवेल, आंजनी और झांझर आदि गांवों को पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही पूर्व निर्मित सेई पिकअप वियर से निकली नहर का भी उपयोग होगा जिससे 276 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विकास होगा।

## उदयपुर : पर्यटन स्थल

राजस्थान में उदयपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध है। अद्वितीय सौन्दर्य एवं प्राकृतिक छटा से सुसज्जित उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि अनेक विशेषण दिये गये हैं। सुन्दर पर्वतमालाओं के मध्य अवस्थित शहर नीले जल से युक्त झीलों में अपनी परछाई निहारते हुए यहां के राजप्रासाद, शीतल समीर के झौंकों से सम्पूर्ण वातावरण को सुवासित करने वाले यहां के पुष्पोद्यान और

मेवाड के शौर्यपूर्ण अतीत का स्मरण कराने वाले यहां के अवशेष निस्संदेह ही उदयपुर को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

उदयपुर नगर की स्थापना महाराणा उदयसिंह ने सन् 1559 में की। यहां पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थान हैं जिनमें अति प्राचीनकाल के इतिहास से संबंधित इमारतें हैं, जो यहां की सांस्कृतिक परम्परा के अनूठे नमूने हैं।

## राजमहल

पिछोला झील के तट पर स्थित उदयपुर नगर में ऊँचे स्थान पर स्थित यहाँ के राजमहल इतने भव्य और विशाल हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें ''राजस्थान के विण्डसर'' महलों की संज्ञा दी। इन महलों से नगर का विहंगम और पिछोला झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। राजमहल में मयूर चौक का सौन्दर्य अनूठा है। चारों ओर काँच को बडी बारीकी एवं कौशल से जमाकर मोर और कुछ मूर्तियां बनाई गयी हैं। यहां बने पांच मयूरों का सौन्दर्य देखते ही बनता है। प्रताप कक्ष में महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्रा, अस्त्रा-शस्त्रा, जिरह-बख्तर आदि संग्रहित हैं। यहीं महाराणा प्रताप का वह ऐतिहासिक भाला रखा है, जिससे हल्दीघाटी युद्ध में आमेर के कुंवर मानसिंह पर प्रताप ने वार किया था।

## जगनिवास

यह महल सन् 1746 में महाराणा जगतसिंह द्वितीय ने बनवाया। यह पीछोला झील के तट से लगभग आठ सौ फीट की दूरी पर झील के मध्य अवस्थित है। इस महल के चारों ओर जल है, जिसके कारण विश्व के सुन्दर महलों में इसकी गणना की जाती है। महल की दीवारों पर बेजोड चित्राकारी नयनाभिराम है।

## जगमंदिर

पीछोला झील के बीच जगनिवास के समानान्तर ही एक दूसरे टापू पर बना है - जगमंदिर महल। यह अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। महल का निर्माण सन् 1615 में महाराणा अमरसिंह प्रथम ने प्रारंभ किया तथा महाराणा करण सिंह ने सन् 1622 में इसे पूरा कराया। इन्हीं महाराणा के पुत्रा जगत सिंह प्रथम ने इसमें कुछ और भाग जोड दिया और इसका नाम बदलकर जग मंदिर रखा।

## जनाना महल

राजमहल के दक्षिण में एक मध्यकालीन भवन है जो मेवाड के महाराणा कर्णसिंह की महारानियों के लिए सन् 1620 में निर्मित किया गया था। महल के अन्दर एक विशाल प्रांगण है। महल के ऊपर बनी जालीदार खिडकियों से हवा और प्रकाश तो मिल ही जाता था, साथ ही रनिवास का पर्दा भी हो जाता था। जनानी ड्योढ़ी से गुजर कर बायें हाथ की ओर रंगमहल में पहुंचा जाता है, जहां राज्य का सोना-चाँदी और खजाना रखा जाता था।

## राजकीय संग्रहालय

राजमहल के ही एक हिस्से में राज्य सरकार का संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक एवं पुरातत्व संबंधी सामग्री का विपुल संग्रह है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहनी जाने वाली पगडियां व साफों के नमूने, सिक्के, उदयपुर के महाराणाओं के चित्रा, अस्त्रा-शस्त्रा व पोशाकों के संग्रह के साथ-साथ शहजादा खुर्रम की वह ऐतिहासिक पगडी भी है जो मेवाड के तत्कालीन महाराणा की दोस्ती में अदला-बदली की गई थी।

## जगदीश मन्दिर

यह मन्दिर राजमहलों के पहले मुख्य द्वार बडी पोल से लगभग 175 गज की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सन् 1651 में महाराणा जगतसिंह प्रथम (1628-53) द्वारा हुआ था। यह 80 फुट ऊँचे प्लेटफार्म पर निर्मित है। मन्दिर में काले पत्थर से निर्मित भगवान जगदीश की भव्य मूर्ति है।

## पिछोला झील

इस झील को चौदहवीं शताब्दी में एक बनजारे द्वारा महाराणा लाखा के समय में बनवाया गया था। कालान्तर में उसके पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार भी हुए हैं। उत्तर से दक्षिण तक करीब साढे चार किलोमीटर चौडी यह झील 10-15 फुट गहरी है। इसकी जल क्षमता 41 करोड 20 लाख घन फुट है। झील के तट पर बने घाट और मन्दिर आकर्षण के केन्द्र हैं।

## फतहसागर

नगर के उत्तर-पश्चिम में करीब 5 कि.मी. दूर यह झील सर्वप्रथम सन् 1678 में महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी, परन्तु एक बार की अतिवृष्टि ने इसे तहस-नहस कर दिया। इसके पुनर्निर्माण का श्रेय महाराणा फतेहसिंह को है जिन्होंने उस समय 6 लाख रुपयों की लागत से इस सशक्त बांध का निर्माण करवाया, उन्हीं के नाम पर झील को फतहसागर कहा जाने लगा।

## नेहरू गार्डन

फतहसागर के मध्य में समुद्रतट से लगभग 1960 फुट ऊँचाई पर स्थित यह उद्यान साढे चार एकड क्षेत्रा में फैला हुआ है। उद्यान की परिधि 2160 फुट है। झील में पानी भरा होने की स्थिति में उद्यान में पहुंचने के लिए झील के किनारे से नियमित नौका सेवा की व्यवस्था उपलब्ध रहती है।

## महाराणा प्रताप स्मारक (मोती मगरी)

फतहसागर के किनारे की पहाडी ''मोती मगरी'' को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। मोती मगरी का बडा ऐतिहासिक महत्व है। उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदयसिंह उदयपुर नगर बसाने के पहले इसी पहाडी पर ''मोती महल'' बनवा रहे थे, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं। इन्हीं खण्डहरों के पास चेतक पर सवार प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है।

## दूध तलाई पार्क

गुलाब बाग के निकट ही माछला मगरा नामक पहाडी की तलहटी में पीछोला झील से सटी हुई एक

तलैया दूध तलाई के नाम से जानी जाती है। यहां एक आकर्षक सीढीदार पार्क स्व. माणिक्यलाल वर्मा के नाम पर नगर परिषद द्वारा विकसित किया गया है। ऊंचाई पर होने के कारण यहां से पीछोला झील व आसपास के क्षेत्रा का विहंगम दृश्य भी बडा खूबसूरत लगता है।

## दीनदयाल उपाध्याय पार्क

दूध तलाई के निकट ही एक पहाडी पर खुबसूरत बगीचा नगर विकास प्रन्यास द्वारा विकसित किया गया है। यहां आकर्षक फव्वारे एवं बगीचे देखने लायक है।

## सहेलियों की बाड़ी

यह उदयपुर का सुन्दरतम् उद्यान है। महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण तथा महाराणा फतहसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यहां राजकुमारियां अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन के लिए आती थीं इसीलिये इसे सहेलियों की बाडी कहा जाता है। यहां फव्वारों की इतनी सुन्दरतम व्यवस्था है कि ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी में भी सावन-भादों का सा आनन्द प्राप्त होता है।

## सुखाड़िया सर्किल

पश्चिम रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के समक्ष स्थित सुखाडिया सर्किल के मध्य में निर्मित 42 फुट ऊँचा फव्वारा देश में अपने ढंग का अनूठा है । फव्वारे के ऊपरी भाग में गेहूँ की विशाल बाली बनाई गयी है।

## रोप-वे

दीनदयाल उपाध्याय पार्क के निकट हाल ही रोप- वे का निर्माण करवाया गया है जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। इसमें दो ट्रोलियां एक साथ दीनदयाल उपाध्याय पार्क के छोर से दूसरी पहाडी पर बने करणीमाता मंदिर छोर तक पर्यटकों को लाती ले जाती है। ट्रॉली में बैठकर पर्यटक शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते है।

## गुलाब बाग

महाराणा सज्जनसिंह द्वारा निर्मित यह एक दर्शनीय स्थल है, इस बाग में लगभग चार सौ प्रकार की वनस्पति पायी जाती है। बाग में बने सरस्वती पुस्तकालय में प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियों एवं ग्रंथों का दुर्लभ संग्रह है। बाग में ही जिले का चिडियाघर (जन्तुआलय) दर्शकों के लिए कौतूहल पैदा करता है। इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए नगर परिषद द्वारा रेल का संचालन भी किया जा रहा है।

## बागोर की हवेली

बागोर की हवेली उदयपुर की पिछोला झील के किनारे स्थित है। इस हवेली का निर्माण मेवाड के शासक महाराणा प्रतापसिंह, महाराणा अरीसिंह, महाराणा हमीरसिंह इत्यादि के कार्यकाल के दौरान 1751 से 1778 के बीच तत्कालीन रियासत के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बडवा द्वारा करवाया गया। श्री अमरचंद बडवा की मृत्यु के बाद यह हवेली रियासत के राज परिवार के अधीन आ गई।

सन् 1878 में महाराणा शक्तिसिंह ने गणगौर घाट पर तीन दरवाजे (त्रिपोलिया) और महल का निर्माण करवाया। इसके बाद 1947 तक यह हवेली मेवाड राज्य की सम्पत्ति रही। स्वाधीनता के पश्चात् राजस्थान सरकार के नियन्त्राण में आई यह हवेली आवास के रूप में उपयोग में भी लाई गई। सन् 1986 में यह हवेली भारत सरकार द्वारा स्थापित पश्चिम क्षेत्रा सांस्कृतिक केन्द्र को हस्तान्तरित की गई। इस केन्द्र की स्थापना पश्चिम भारत के राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोआ की कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के ध्येय से की गई।

## हवेली संग्रहालय

उदयपुर में पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर स्थित बागोर की हवेली में 'हवेली संग्रहालय' बनाया गया है। बागोर की हवेली के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे प्राचीन स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए 1992 में इसका कायाकल्प किया गया। संग्रहालय की स्थापना का मुख्य ध्येय मेवाड के राजसी वैभव को 'हवेली संस्कृति' के प्रतीक रूप में दर्शाना है।

## शिल्पग्राम

''शिल्पग्राम'' अर्थात् हस्तशिल्पियों का गांव उदयपुर से 3 किलोमीटर पश्चिम में हवाला गांव में स्थित है, जो अपने आप में एक जीवंत संग्रहालय है, यहां असाधारण विविधता, ललित कला, वास्तुशिल्प को समेटे हुए कई झोंपडियों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ आदि राज्यों की परम्परागत कलाशिल्प तथा संस्कृति को दिग्दर्शित कराता है। यह परिसर लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। मृणशिल्प और मुखौटा संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, कोठी संग्रहालय, मूर्ति शिल्प, उद्यान तथा प्रतिदिन चौपाल पर होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां शिल्पग्राम का विशेष आकर्षण हैं।

## भारतीय लोक कला मण्डल

भारतीय लोक कला मण्डल देश विदेश में अपने नाट्य नृत्य एवं कठपुतली प्रदर्शनों से विशिष्ट ख्याति अर्जित कर चुका है। इस संस्थान में स्थापित संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों, आभूषणों तथा पोशाकों का संग्रह है। साथ ही लोक कला संबंधित विभिन्न विषयों के चित्रा, मूर्तियां, मॉडल इत्यादि का सुंदर प्रदर्शन पर्यटकों को आकर्षित करता है।

## आहाड़

सिसोदिया राज की प्राचीन राजधानी आहाड (आयड) उदयपुर से तीन किलोमीटर दूर स्थित है। आहाड में मेवाड शासकों के शाही स्मारकों (छतरियों) की प्रचुरता व गौरव है। यहां प्राचीन कलाकृतियों का दुर्लभ संग्रह-मिट्टी के बर्तन, लोहे की वस्तुएं व प्रदेश की खुदाई में निकली अन्य कलात्मक एवं पुरातत्व महत्व की वस्तुएं आहाड संग्रहालय में प्रदर्शित हैं।

## ऐतिहासिक सज्जनगढ़

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदयपुर शहर के निकट ऊँचाई पर बांसदरा पहाडियों पर सज्जनगढ वन्य

जीव अभयारण्य के मध्य स्थित सज्जनगढ़ किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। आस-पास के क्षेत्रा से 1100 फुट की ऊँचाई पर स्थित इस किले का निर्माण स्व. महाराणा सज्जनसिंह द्वारा उनके ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु कराना प्रारम्भ किया गया । तदन्तर महाराणा फतेहसिंह द्वारा महल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इस महल में स्त्रियों हेतु अलग से प्रवास सुविधा, एक बडा प्रवेश द्वार तथा चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ दीवार का निर्माण कराया गया है । उदयपुर शहर की यह गौरवमयी ऐतिहासिक संरचना किसी भी दिशा से शहर में प्रवेश करते ही देखी जा सकती है। यहां से सम्पूर्ण उदयपुर शहर का दृश्यावलोकन किया जा सकता है । वर्षा ऋतु में इस महल से उदयपुर शहर एवं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेते हैं।

## उदयसागर

उदयपुर के पूर्व में लगभग 13 कि.मी. दूरी पर स्थित इस झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदयसिंह ने सन् 1559 से सन् 1565 के मध्य करवाया था। झील लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्रा में फैली है।

## जयसमन्द झील

यह झील उदयपुर नगर से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। यह विश्व की विशालतम मानव निर्मित झीलों में से एक है। महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया। यह झील महाराणा जयसिंह के नाम पर जयसमंद (जयसमुद्र) मानी जाती है। मनोरम दृश्यावली से आवृत्त यह झील बहुत ही उत्कृष्ट पर्यटन स्थल है। इसके किनारे पर नर्मदेश्वर महादेव का मन्दिर है। इसके उत्तर में एक पुराना महल है, जिसकी दीवारों पर कुछ चित्रा भी बने है। इसके पास की दो पहाडियों पर महाराणा जयसिंह द्वारा बनाये गये दो पुराने महल हैं। इन महलों से झील का दृश्य बडा सुन्दर लगता है।

## नागदा

उदयपुर शहर से 23 कि.मी. दूर स्थित है। यह छठी शताब्दी का प्राचीन स्थल है यहां नवीं शताब्दी में निर्मित सहस्रबाहु (सास-बहू) मन्दिर के अवशेष देखे जा सकते हैं।

## जगत

जिला मुख्यालय से 58 किलोमीटर दूर शानदार व अच्छे ढंग से परिरक्षित स्थल है। 10वीं सदी का अम्बिका माता मन्दिर बाहरी दीवारों पर अपनी बेजोड़ नक्काशी के लिए विख्यात है। जगत को 'राजस्थान का खजुराहो' भी कहा जाता है।

## ऋषभदेव

यहां आदनाथ अथवा ऋषभदेव का प्रसिद्ध पौराणिक एवं प्राचीन मन्दिर है। यहां प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री आते हैं। मन्दिर में बडी महीन नक्काशी की गई है। यह अपनी पुरातात्विक सुन्दरता तथा आकर्षण के लिये प्रसिद्ध है।

# एकलिंगजी (कैलाशपुरी)

यह उदयपुर नगर से 31 किलोमीटर दूर है। यहां राणा रायमल द्वारा बनवाया गया शिल्प वैविध्य भरा कलात्मक मन्दिर काफी दर्शनीय है। मन्दिर में काले संगमरमर की बनी एकलिंगजी(महादेव) की पंचमुखी मूर्ति है। इस मूर्ति के सामने श्रद्धावनत् अवस्था में महाराणा भीमसिंह की एक मूर्ति बनी है। मन्दिर के प्रांगण में एकलिंगजी के मन्दिर के चारों ओर अनेक देवी-देवताओं की छोटी-छोटी मूर्तियां हैं। इनमें से एक मन्दिर भगवान विष्णु का है जो राणा कुम्भा द्वारा बनवाया गया तथा 'मीराबाई मन्दिर' के नाम से प्रसिद्ध है।

# चावण्ड

उदयपुर 35 किलोमीटर दूर चावण्ड ग्राम है, जहां एक जैन मंदिर है । यहीं 19 जनवरी, 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। चावण्ड से लगभग दो किलोमीटर दूर बडोली गांव के निकट बहने वाले एक छोटे नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार हुआ।

# राजीव गांधी उद्यान

झीलों की नगरी उदयपुर कि प्रसिद्ध फतहसागर झील के दक्षिण-पश्चिम छोर पर नगर विकास प्रन्यास,उदयपुर द्वारा राजीव गांधी स्मृति उद्यान का निर्माण करवाया गया हैं। राजीव गांधी स्मृति उद्यान का निर्माण कुल 12 एकड भूमि में कराया गया हैं। जो कि वर्ष 2003 में प्रारंभ होकर 2007 में पूर्ण किया गया। इसकी कुल लागत रु.300-00 लाख आयी हैं।

राजीव गांधी स्मृति उद्यान के अंदर मुख्यतः मूर्ति स्थल, मेन फाउन्टेन चौक, बारादरी, वाटर चेनल, फुटपाथ एवं प्लान्टर्स आदि का निर्माण किया गया। इसमें पर्यटकों की सुविधा एवं मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए फूडकोर्ट, चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण किया गया तथा मूर्ति स्थल पर अष्टधातु से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्राी स्व.राजीवगांधी कि आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई हैं। उद्यान में फाईबर निर्मित 7 प्रकार के रेयर वाईल्ड एनिमल लगाये गये है, जिनमें की 5 रुपये का सिक्का डालने पर अपने बारे में जानकारी देते है तथा चिल्ड्रन पार्क में एजुकेशनल डकोरेटिव पोल लगाकर उन पर लाइटें लगायी गई हैं, जो कि हमारे सौर मण्डल, मेवाड़ तथा राजस्थान से संबंधित जानकारी फोटोग्राफ सहित लिखित में जानकारी देते हैं। जो देशी-विदेशी एवं स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।